



NEERAJ®

MGPE - 13

नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष

(Civil Society, Political Regimes and Conflicts)

**Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers**

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Manish Kumar



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

**नागरिक समाज, राजनीतिक
शासन तंत्र और संघर्ष**
(**Civil Society, Political Regimes and Conflicts**)

Question Paper—June-2024 (Solved)	1
Question Paper—December-2023 (Solved)	1
Question Paper—June-2023 (Solved)	1-2
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved)	1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved)	1
Question Paper—December, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2017 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
1.	नागरिक समाज की समझ (Understanding of Civil Society)	1
2.	नागरिक समाज के तत्त्व (Elements of Civil Society)	12
3.	नागरिक समाज : स्थानीय और वैश्विक (Civil Society : Local and Global)	22
4.	गाँधी तथा स्वैच्छिकतावाद (Gandhi and Voluntarism)	30
5.	राज्य और नागरिक समाज का मिलन-बिन्दु (Interface of Civil Society and State)	38

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
6.	वैश्वीकृत बाजार में नागरिक समाज (Civil Society in Globalised Market)	46
7.	नागरिक समाज और राजनीतिक शासन (Civil Society and Political Regimes)	53
8.	नागरिक समाज, प्रतिरोध और विरोध (Civil Society, Resistance and Protest)	61
9.	वैश्विक शान्ति आन्दोलन (Global Peace Movements)	71
10.	शान्ति प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका (Role of NGOs in Peace Process)	81
11.	शान्ति के लिए मानव अधिकार और संस्कृति (Human Rights and Culture for Peace)	91
12.	भारत में शान्ति आन्दोलन (Peace Movements in India)	101
13.	गाँधी, क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण (Gandhi, Capacity Building and Empowerment)	109
14.	आधारिक/जनपहल (Grassroots/People's Initiatives)	118
15.	स्वैच्छिक कार्य का संगठन (Mobilising Voluntary Action)	128
16.	वैश्विक शान्ति के लिए गाँधीवादी नागरिक समाज (Gandhian Civil Society for Global Peace)	140



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष
(Civil Society, Political Regimes and Conflicts)

MGPE-13

समय : 2 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 50

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में से कम से कम दो प्रश्न चुनते हुए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग - अ

प्रश्न 1. शांति आंदोलनों के उद्भव और विकास का पता लगाइये।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-12, पृष्ठ-104, प्रश्न 2

प्रश्न 2. क्षमता निर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-13, पृष्ठ-111, 'क्षमता निर्माण'

प्रश्न 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकेन्द्रीकरण की विशेषताओं का परिगणन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-14, पृष्ठ-126, प्रश्न 5

प्रश्न 4. स्थानीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने के कारकों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-15, पृष्ठ-129, 'स्थानीय संस्थाओं की जवाबदेही कैसे?'

प्रश्न 5. शांति के लिए नागरिक समाज की गाँधीवादी धारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-16, पृष्ठ-143, 'गाँधीवादी नागरिक समाज : वैश्विक शान्ति का जवाब'

भाग - ब

प्रश्न 6. राज्य और नागरिक समाज पर हीगेल के विचारों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-5, पृष्ठ-41, प्रश्न 1

प्रश्न 7. नागरिक समाज पर ग्रामस्की के विचारों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-2, पृष्ठ-16, प्रश्न 2

प्रश्न 8. वैश्विक नागरिक समाज क्या है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-3, पृष्ठ-23, 'वैश्विक नागरिक समाज का अर्थ'

प्रश्न 9. आत्मनिर्भर और स्वशासन के रूप में स्वराज की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-4, पृष्ठ-31, 'स्वनिर्भरता और स्वशासन के रूप में स्वराज'

प्रश्न 10. बहुलवादी राज्य पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-5, पृष्ठ-39, 'बहुलवादी राज्य'



QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष
(Civil Society, Political Regimes and Conflicts)

MGPE-13

समय : 2 घण्टे /

/ अधिकतम अंक : 50

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में से कम से कम दो प्रश्न चुनते हुए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग - I

प्रश्न 1. नागरिक समाज और राज्य विरोध पर थॉमस पेन के विचारों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-1, पृष्ठ-3, 'नागरिक समाज और राज्य में विरोध : पेने', पृष्ठ-9 प्रश्न 5

प्रश्न 2. नागरिक समाज पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् के वाद-विवाद का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-2, पृष्ठ-20, प्रश्न 5

प्रश्न 3. व्यक्ति की स्वायत्तता पर गांधीजी के विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-4, पृष्ठ-30, 'व्यक्ति की स्वायत्तता'

प्रश्न 4. उन्नत पूँजीवादी राज्य पर क्या विवाद है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-5, पृष्ठ-44, प्रश्न 1

प्रश्न 5. बाजार, राज्य और नागरिक समाज के बीच बदलते संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-6, पृष्ठ-49, प्रश्न 2

भाग - II

प्रश्न 6. एशिया और नागरिक समाज की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-7, पृष्ठ-57, प्रश्न 2

प्रश्न 7. विरोध और प्रतिरोध की विशेषता के रूप में अहिंसा की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-8, पृष्ठ-68, प्रश्न 2

प्रश्न 8. परमाणु युग शांति संस्थान (एन.ए.पी.एफ.) पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-9, पृष्ठ-77, प्रश्न 4

प्रश्न 9. शांति प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-10, पृष्ठ-81, 'गैर-सरकारी संगठन किसे कहते हैं'?

प्रश्न 10. मानव अधिकारों की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास का पता लगाइए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अभ्यास-11, पृष्ठ-97, प्रश्न 2



Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष (Civil Society, Political Regimes and Conflict)

नागरिक समाज की समझ (Understanding of Civil Society)



परिचय

नागरिक समाज की अवधारणा का उदय 1750 से 1850 के मध्य हुआ। प्रारंभ में नागरिक समाज को राज्य का ही पर्याय माना जाता था, परन्तु बाद में राज्य और नागरिक समाज को भिन्न-भिन्न अवधारणा माना गया। नागरिक समाज की अवधारणा का जन्म स्वेच्छाचारिता के उन्मूलन के उद्देश्य से हुआ। नागरिक समाज की अवधारणा सबसे पहले अरस्तू के राजनीतिक दर्शन यूनानी शब्द (Politika Koinonia) में देखने को मिलती है। अरस्तू नागरिक समाज को समान नागरिकों का नैतिक-राजनीतिक समुदाय मानता है। नागरिक समाज की अवधारणा को हम आधुनिक मान सकते हैं, परन्तु इसका उल्लेख हमें प्राचीन राजनीतिक दर्शन में भी मिलता है। नागरिक समाज को 18वीं शताब्दी की लोकतान्त्रिक क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग से नागरिक समाज को परिभाषित करने का प्रयास किया है इसी कारण नागरिक समाज पर एक सर्वमान्य परिभाषा का अभाव दिखता है।

यह अध्याय नागरिक समाज के विभिन्न पहलुओं से हमें अवगत कराता है। इस अध्याय के अंतर्गत अरस्तू और नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा, उत्तर-अरस्तू कालीन उद्विकास, नागरिक समाज की प्रारंभिक आधुनिक धारणा: फर्ग्यूसन और स्कॉटिश प्रबोधन, नागरिक समाज और राज्य में विरोध: पेने, राज्य के प्राण तत्त्व के रूप में नागरिक समाज : टोकवील्ले तथा सार्वभौमिक राज्य और विशिष्ट नागरिक समाज : हीगल आदि की चर्चा की गई।

अध्याय का विहंगावलोकन

अरस्तू और नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा

अरस्तू ने अपने लेखन में koinonia शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें समिति, समुदाय तथा समाज की अवधारणाएं शामिल हैं। रनसिमैन के अनुसार “अरस्तू का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक और राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों के बीच अन्तर करना है।” अरस्तू द्वारा प्रस्तुत विभेदों की शृंखला राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज के मध्य के अन्तर को स्पष्ट करती है। अरस्तू के अनुसार प्राकृतिक समितियों में राज्य सबसे उच्च होता है। राज्य गृहस्थी से भिन्न होता है। गृहस्थी या परिवार से मिलकर एक गाँव बनता है तथा अनेक गाँव मिलकर नागरिक समाज का निर्माण करते हैं।

राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए होता है। राज्य की स्थापना समितियों या संघों (associations) के साध्य के रूप में होती है। राज्य का अस्तित्व स्वभाव से होता है, जो व्यक्ति राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं करता, वह मनुष्य नहीं हो सकता है। राज्य और परिवार (कुटुम्ब) एक समान नहीं होते हैं। राज्य परिवार एवं व्यक्ति से पहले होता है। एक परिवार बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है जबकि एक राज्य व्यक्ति के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। किसी राज्य में जीवन की गुणवत्ता उस राज्य में रहने वाले लोगों एवं उनके लक्ष्यों पर निर्भर करती है। अरस्तू के अनुसार संविधान जीवन जीने का एक तरीका होता है, क्योंकि संविधान राज्य के नैतिक चरित्र को निर्धारित करता है। प्लेटो ने

2 / NEERAJ : नागरिक समाज, राजनीति शासन तंत्र और संघर्ष

परिवार को राज्य में शामिल किया है, जिसकी अरस्तू ने आलोचना की है। अरस्तू परिवार एवं राज्य को भिन्न मानता है। परिवार (कुटुम्ब) में पति-पत्नी, स्वामी-सेवक तथा बच्चों के मध्य सम्बन्ध होते हैं। जबकि राज्य में शासक एवं शासित के मध्य समानता का सम्बन्ध होता है। इसी मत को जॉन लॉक (1632-1704) ने राजनीतिक निरंकुशतावाद की अपनी आलोचना में दोहराया है। राज्य को स्वतंत्र पुरुषों का स्थान माना गया है। अरस्तू के अनुसार polis उन स्वतंत्र एवं समान पुरुषों का संघ होता है, जो मित्रता एवं न्याय की दृष्टि से बँधे होते हैं।

उत्तर-अरस्तूकालीन उद्विकास

अरस्तू का कहना है कि “केवल गुणवत्ता के सिद्धान्त, संख्या की गुणवत्ता तथा जन-साधारण के दावों के तत्त्वों में सन्तुलन स्थापित करके ही राज्य को स्थिर किया जा सकता है तथा उसे क्रान्तियों की चपेट में आने से बचाया जा सकता है।” अरस्तू मध्य वर्ग को समाजगत सन्तुलन के एक साधन के रूप में देखता है। अरस्तू मानता है कि मध्य वर्ग ही राज्यतंत्र है तथा यह समानता एवं सर्वसम्मति को पूरा करता है। मिश्रित संविधान के इस आदर्श को निम्नलिखित विद्वानों ने महत्त्व दिया है—पोलिबियस (263-120 ई.पू.), मार्कुस टुलियस सिसरो (106-43 ई.पू.), सेंट टॉमस अक्विनास (1224-74 ई.), निकोलो मैकियावेली (1527-1649 ई.) तथा एडम स्मिथ (1723-90 ई.)।

उत्तर-अरस्तूकालीन दौर में समबुद्धिवादियों ने विश्व नागरिकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। रोमन साम्राज्य ने समस्त मनुष्यों को इस अवधारणा के अन्तर्गत एकजुट करने का प्रयास किया। अरस्तू ने जिस एकता पर बल दिया था वह ईसाई धर्म के विकास से खण्डित हो गई। अरस्तू ने नागरिक सभा को चर्च से अलग कर दिया। अरस्तू ने दोहरी नागरिकता का भी सृजन किया। ईसाई धर्म सामाजिक एकता के लिए आत्मिक सहभागिता पर अधिक बल देता है। ‘मनुष्य समूह’ की परिभाषा अगस्टीन ने दी है। अगस्टीन की दृष्टि में रोमन गणतंत्र ईश्वर के प्रेम से बँधा हुआ एक समुदाय है। अक्विनास की रचनाओं में अरस्तू की धारणा पुनर्जीवित होती है, क्योंकि इसमें राज्य को एक संगठन के रूप में देखा गया है। अक्विनास की दृष्टि में समुदाय तथा समाज एक-दूसरे के पर्याय हैं। आलीग्येरी दांते (1265-1321) ने एक सन्तुलित और पूर्ण द्वैतवाद को प्रस्तुत किया है। जिसमें राज्य एवं चर्च स्वतंत्र होकर भी एक-दूसरे के पूरक माने गये हैं। सामंती समाज में समाज रियासतों, समुदायों तथा संघों में विभाजित था, परन्तु अब समुदाय तथा समाज की धारणाओं का उल्लेख राजनीतिक समाज के अन्तर्गत होता है।

नागरिक समाज की प्रारंभिक आधुनिक धारणा : फर्ग्यूसन और स्कॉटिश प्रबोधन

नागरिक समाज का उदय सामंती समाज के विघटन के साथ ही हुआ। राजनीतिक समाज तथा आध्यात्मिक समाज के मध्य अन्तर

का मुद्दा तब उभरा, जब ईसाई धर्म की एकता भंग हो गई, जिसका कारण प्रोटेस्टैंट मत का जन्म था। टॉमस हॉब्स (1588-1679) ने चर्च-केन्द्रित सत्ता को शिक्षण और प्रेरणा माना है। हॉब्स के अनुसार केवल राज्य की क्रियाओं के द्वारा ही धार्मिक सिद्धान्तों को राजनीतिक दर्जा प्राप्त हो सकता है। लॉक के अनुसार राजनीतिक शासन पैतृक नहीं होता है। हॉब्स तथा लॉक दोनों ही विद्वान नागरिक समाज की विशिष्टताओं को वापस प्रकृति की स्थिति में ले जाने का प्रयास करते हैं।

राजनीतिक और सामाजिक के बीच भेद का जन्म—19वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य और समाज का एक और भेद हमारे सामने आया। नागरिक समाज अब अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को अपने ही ढंग से पूरा करने के अधिकार का प्रयोग करता है। चार्ल्स-लूई एस. मॉन्टेस्क्यू (1689-1755) के अनुसार वाणिज्यवाद मनुष्यों को उनके पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है, जो मनुष्य अपनी वास्तविक आवश्यकता को समझ लेता है वह मानवता के बोध को भी जान लेता है। यदि मनुष्य शान्तिपूर्ण व्यापार के आकर्षण को समझ ले तो उसे सैनिक अभियानों तथा युद्ध से नफरत हो जायेगी। वे राष्ट्रीय विविधता को समझने लगेंगे। वाणिज्य तो न्यायिक समाधान की भावना को लेकर आता है, जिससे हितों के बीच एक सन्तुलन स्थापित हो जाता है।

डेविड ह्यूम (1711-76) हित को व्यक्ति को समाज से जोड़ने वाला कारक मानता है। एडम स्मिथ ने सहयोग को समाज-निर्माण का आधार माना है। इस सन्दर्भ में स्वार्थ, संवेग तथा झगड़ों को भी ध्यान में रखना होगा। नागरिक समाज का गठन अनुबंध से भी होता है, जिसके लिए न्याय एवं विश्वास की आवश्यकता होती है। स्कॉटिश प्रबोधन के चिन्तकों ने नागरिक समाज का एक नया वर्णन प्रस्तुत किया है। इन चिन्तकों ने नागरिक समाज की उस पारंपरिक अवधारणा को तोड़ने का प्रयास किया है जिसे सामाजिक अनुबंध चिन्तक मानते थे। इन चिन्तकों की दृष्टि में आर्थिक व्यवस्था अब नागरिक समाज का एक अहम हिस्सा बन गई है, यह विचार पडुआ के मार्सिलियस (1275-1342) की रचनाओं से लिया गया है, जिसके अनुसार भौतिक शान्ति से ही आर्थिक लाभों का आदान-प्रदान संभव होता है।

नागरिक समाज का विस्तृत विश्लेषण फर्ग्यूसन के ‘ऐन एसे ऑन दी हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसायटी (1767)’ में प्रस्तुत किया गया है। फर्ग्यूसन ने राज्य और नागरिक समाज को एक समान माना है। नागरिक समाज एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जो कानून एवं सैनिक शक्ति के द्वारा कलाओं को, सांस्कृतिक उपलब्धियों को तथा जनभावना के बोध को निखारती है। फर्ग्यूसन कानून के विभाजन को जन-भावना को भ्रष्ट करने वाला मानता है। जन-भावना के हास से स्वेच्छाचारी शासन का मार्ग प्रशस्त होता है। जब नागरिक समाज जन-भावना को नष्ट कर देता है तो इससे राज्य की शक्ति बढ़ती

है। नागरिक समाज सैनिक शक्ति को भी स्थापित करता है, जिससे सैनिक शक्ति के बल पर सरकार बनाने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार के समाधान के लिए नागरिक समाज को एक सम्प्रभु केन्द्रीकृत संवैधानिक राज्य की आवश्यकता होती है। फर्ग्यूसन ने भी नागरिक समाज को मजबूत करने के लिए नागरिक समितियों को मजबूत करने का सुझाव दिया है। फर्ग्यूसन कहता है कि मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामाजिक समूहों में करते हैं। फर्ग्यूसन जन-भावनायुक्त संवैधानिक राजतंत्र को सर्वोत्तम मानता है। संवैधानिक राजतंत्र में मुख्य जोर नागरिक समाज और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर होता है।

नागरिक समाज और राज्य में विरोध : पेने

नागरिक समाज के सन्दर्भ में दूसरे चरण की शुरुआत तब होती है जब 'राइट्स ऑफ मैन' में एडमंड बर्क (1729-97) के विचारों का पेने ने खण्डन किया। पेने ने नागरिक समाज के पक्ष में राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने की बात कही है। पेने राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, जबकि नागरिक समाज अबाधित अच्छाई। पेने के अनुसार नागरिक समाज जितना अधिक सक्षम होगा उतना ही वह अपने कार्यों पर नियंत्रण रख सकेगा। पेने यह मानता है कि अमेरिका के अलावा सभी जगह राज्य अपनी जनता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सरकारें जनता पर अधिक कर लगाकर समाज के भीतर वर्ग विभाजन को उत्पन्न कर देती हैं। पेने यह मानता है कि राज्य की शक्ति को कम करके नागरिक समाजों के एक अन्तर्राष्ट्रीय परिसंघ के गठन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

पेने यह मानता है कि राज्य ही वैश्विक व्यवस्था तथा सद्भाव को संभव बनाते हैं। नागरिक समाज साझा हितों पर विकसित होता है तथा सरकार द्वारा निर्मित कानूनों से सशक्त बनता है। व्यक्ति दूसरों के साथ सहज ही परस्पर व्यवहार करते हैं, जो एक आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में सहायक है।

पेने ने राज्य की ज्यादतियों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पेने के अनुसार सहमति और अधिकार एक वैध राज्य को निर्देशित करते हैं। किसी भी राजनीतिक समूह तथा संस्था को यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि विश्व किसके द्वारा शासित होगा, क्योंकि जन्म से सभी व्यक्ति समान होते हैं तथा वे समान अधिकारों से सम्पन्न होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा मिले होते हैं। राज्य की वैधता का आकलन हम नैसर्गिक अधिकारों से कर सकते हैं। इनका हस्तांतरण या विभाजन भी नहीं किया जा सकता है। पेने यह मानता है कि राज्य केवल तभी वैध एवं सभ्य होते हैं जब उनका गठन व्यक्तियों की सहमति से होता है। नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्य होते हैं अधिकार नहीं। सरकार संविधान के अधीन होती है। संविधान से रहित सरकार उसी प्रकार है, जिस प्रकार अधिकार से रहित सत्ता। संविधान का सरकार से वैसा ही सम्बन्ध होता है जैसा कानूनों का सम्बन्ध न्यायिक अदालत

से होता है। न्यायिक अदालत केवल कानूनों का पालन करती है। इसी प्रकार सरकार भी संविधान से ही शासित होती है।

राज्य के प्राण तत्त्व के रूप में नागरिक समाज : टोकवील्ले

टोकवील्ले (1805-59) के अनुसार आधुनिक देशों के समक्ष एक समस्या स्वेच्छाचारी राज्य की है, जिसका समाधान नागरिक समाज के विकास से ही हो सकता है। लोकतान्त्रिक क्रान्ति की दृढ़ता के लिए नागरिक समितियों की अधिकता आवश्यक है। टोकवील्ले के अनुसार नागरिक समितियाँ मुक्त विद्यालय हैं, जिसमें नागरिक अपने अधिकारों एवं दायित्वों को सीखते हैं। टोकवील्ले की दृष्टि में नागरिक समितियाँ वे समितियाँ हैं, जिनमें व्यक्ति अपना ध्यान अपने स्वार्थों तथा निजी लक्ष्यों से हटाकर सहयोग की दिशा में लगा सकते हैं। टोकवील्ले मानता है कि राज्य संस्थाएँ नागरिक समितियों में अस्तित्व और समन्वय को सुनिश्चित करती हैं। टोकवील्ले मानता है कि लोकतंत्र के विकास के लिए एक संगठित नागरिक समाज की अत्यंत आवश्यकता है, जो राज्य से स्वतंत्र हो। टोकवील्ले ने तीन भाग वाला एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें राजनीतिक समाज तथा राज्य के प्रशासनिक तंत्र का अन्तर स्पष्ट किया गया है।

सार्वभौमिक राज्य और विशिष्ट नागरिक समाज : हीगल

हीगल ही वह विद्वान थे जिन्होंने राज्य और नागरिक समाज के मध्य अन्तर के बारे में विस्तृत रूप से लिखा। मैन्फ्रेड रीडल के अनुसार "नागरिक समाज के सम्बन्ध में हीगल की अवधारणा की तुलना बाँदें की 'सम्प्रभुता की अवधारणा' तथा रूसो की जन-इच्छा (General will) की धारणा से की जा सकती है।" हीगल ने Bürgerliche Gesellschaft को राजनीतिक दर्शन की बुनियादी अवधारणा के साथ रखा, जो बाँदें की, मीलैन्थन की, वुल्फ की तथा कांट की Bürgerliche Gesellschaft की परंपरा के अनुरूप ही है। हम यह कह सकते हैं कि हीगल से पहले आधुनिक अर्थ में नागरिक समाज की अवधारणा का अस्तित्व नहीं था।

परन्तु कीन ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। कीन के अनुसार 1750 से 1850 के मध्य अनेक अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा जर्मन चिन्तकों का नागरिक समाज की अवधारणा से सरोकार था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन में कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों ने नागरिक समाज की अवधारणा को प्रभावित किया। ये घटनायें थीं—एक सफल क्रान्ति का अभाव, राष्ट्र-राज्य का ढांचा देर से बनना, उपभोक्ता वस्तुओं का धीमा उत्पादन, संसदीय शासन की अशक्तता, राजनीतिक संस्कृति का कमजोर होना इत्यादि।

हीगल ने राज्य और नागरिक समाज को भिन्न-भिन्न माना है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में ही निजी व्यक्तियों की सम्पूर्णता मूर्त रूप लेती है। नागरिक समाज को बुर्जुआ समाज माना गया है।

4 / NEERAJ : नागरिक समाज, राजनीति शासन तंत्र और संघर्ष

जो निजी, स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों का समाज होता है। हीगल की दृष्टि में नागरिक समाज हितों के टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। हीगल, नागरिक समाज को अपंग करने वाला समाज मानता है। हीगल नागरिक समाज को नैतिक जीवन का ऐतिहासिक रूप से उपजा क्षेत्र मानता है। जो परिवार एवं राज्य के बीच स्थित होता है, जिसमें बाजारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक वर्ग, निगम तथा संस्थाएँ शामिल होती हैं। नागरिक समाज की उत्पत्ति आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

हीगल के अनुसार बुर्जुआ समाज उन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है, जो मानव श्रम के यंत्रीकरण तथा विशेषीकरण के एक स्तर को आवश्यक बना देता है। हीगल कहता है कि नागरिक समाज के अन्दर समरसता की कोई संभावना नहीं होती है। यह समरसता केवल परिवार में ही पाई जा सकती है। नागरिक समाज में सम्बन्ध नाजुक होते हैं। नागरिक समाज में कभी-कभी टकराव के कारण अशान्ति भी उत्पन्न हो जाती है। हीगल ने नागरिक समाज में निम्नलिखित वर्गों की उपस्थिति स्वीकार की है—लोक-सेवक, भूस्वामी, बुद्धिजीवी या विद्वान, वकील, डॉक्टर तथा पुरोहित। हीगल का विश्लेषण फर्ग्यूसन के ही समान है। हीगल ने कामगारों को बर्बर वर्ग में सम्मिलित किया है। यह वर्ग सामूहिक समितियों पर निर्भर करता है, यह वर्ग कम जन-भावना से युक्त होता है। हीगल, फर्ग्यूसन और पेने के इस विचार से सहमत हैं कि आधुनिक नागरिक समाज लेन-देन करने वाले व्यक्तियों की एक जटिल व्यवस्था है, परन्तु हीगल नागरिकता के सम्बन्ध में फर्ग्यूसन के विचारों को तथा नैसर्गिक सामाजिकता के सन्दर्भ में पेने के विचारों का खण्डन करता है, जो नागरिक समाज को एक अस्थिर क्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए नागरिक समाज विशिष्टता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सामाजिक अन्यायों तथा असमानताओं को मिटाने के लिए राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भी नागरिक समाज में हस्तक्षेप कर सकता है।

कीन के अनुसार नागरिक समाज के सन्दर्भ में हीगल का विश्लेषण नागरिक समाज की अवधारणा के तीसरे चरण को प्रारंभ करता है। मार्क्स राज्य और नागरिक समाज के सम्बन्ध की आलोचना करता है। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज तो घोर भौतिकवाद की, संघर्ष की, सम्पत्तिगत सम्बन्धों की तथा अहंवाद की स्थली है। मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज का जन्म मध्ययुगीन समाज के नष्ट हो जाने से हुआ है। मार्क्स के अनुसार मध्ययुग में नागरिक समाज जैसी किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति कई समाजों (श्रेणी, रियासत) का हिस्सा था। इन समाजों के नष्ट हो जाने पर ही नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई है। मार्क्स के अनुसार कानून मनुष्य की इच्छा से नहीं आता। आधुनिक राज्य के स्वरूप को नागरिक समाज की खण्डित प्रगति ही तय करती है।

एंटीनियो ग्राम्स्की ने नागरिक समाज शब्द का प्रयोग मार्क्स से भिन्न ढंग से किया है। ग्राम्स्की के अनुसार यह संगठनों का क्षेत्र है, जिसमें स्व-विनियमन तथा स्वतंत्रता की संभावना होती है। मार्क्स राज्य और नागरिक समाज को पृथक् मानता है, परन्तु ग्राम्स्की ने दोनों को परस्पर सम्बन्धित माना है। स्कूल, चर्च, क्लब, पत्रिकाएँ तथा पार्टियाँ जैसी निजी संस्थाएँ नागरिक समाज के अन्तर्गत आती हैं। जबकि सरकार, अदालतें, पुलिस तथा सेना जैसी सार्वजनिक संस्थाएँ राजनीतिक समाज के अन्तर्गत आती हैं। नागरिक समाज की संस्थाएँ राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को सुदृढ़ करती हैं जबकि राजनीतिक समाज की संस्थाएँ वर्चस्व का माध्यम बनती हैं। बुद्धिजीवी वर्ग नागरिक समाज में ही प्रधानता कायम करता है। मार्क्स ने आर्थिक सम्बन्धों पर अधिक जोर दिया है जबकि ग्राम्स्की ने अधीरता पर। वर्चस्वशाली वर्ग की प्रधानता का परिपालन नागरिक समाज के द्वारा सांस्कृतिक रूप से होता है, परन्तु नागरिक समाज की यह प्रधानता सभी समाजों में एक समान नहीं पाई जाती है। सोवियत संघ की स्थिति के बारे में ग्राम्स्की लिखता है कि “रूस में राज्य ही सब कुछ था, नागरिक समाज तो वहाँ आदिकालीन था। पश्चिम में राज्य और नागरिक समाज के मध्य मजबूत सम्बन्ध था इसलिए राज्य जब अस्थिर हुआ तो नागरिक समाज का मजबूत ढाँचा तुरन्त प्रकट हो गया।”

ओ' डोनेल, कोलकोव्स्की, मलयनार, वाज़दा मिचनिक, हेबरमास, लिफोर्ट, टूरन, बोबियो, बेफर्ट तथा कार्डोसो जैसे नव-मार्क्सवादी विद्वानों के विचारों में नागरिक समाज की अवधारणा पुनः प्रकट होती है। इन विचारों में एकदलीय शासन पद्धति की उत्पत्ति का पता लगाया गया है। हीगल ने नागरिक समाज और राज्य के बीच एकता की बात कही है, परन्तु ऑगस्ट मारी फ्रांस्वा कॉम्टे (1798-1857) ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने के प्रयास में हीगल की इस बात को खारिज कर दिया है। समाजशास्त्र ऐसा विषय है, जो सामाजिक गतिकी तथा सामाजिक स्थैतिकी का विश्लेषण करता है।

बोध-प्रश्न

प्रश्न 1. नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि किन कारणों से इसका विघटन हुआ।

उत्तर—नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा का विकास अरस्तू ने किया था। अरस्तू का काल लगभग 384 ई.पू. से 322 ई.पू. तक माना जाता है। अरस्तू ने अपने लेखन में जिस यूनानी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है, उस दृष्टिकोण में कई बार koinonia शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में कई प्रकार की धारणाएँ सम्मिलित थीं, जैसे—समिति, समुदाय तथा समाज की अवधारणाएँ। अरस्तू के लेखों में इन धारणाओं के लिए किसी अलग शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। रनसिमैन इस सन्दर्भ में कहता है कि “अरस्तू